पंचतत्व में विलिन हुई
केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत

हिन्दी साप्ताहिक

हर्षिता टाइम्स

RNI Regn. No. UTTHIN/2008/28646

40 साल बाद वियना में पहली भारत-ऑस्ट्रिया
मुलाकात, तस्वीरों में

• वर्ष : 16 • अंक : 27 • देहरादून • वृहस्पतिवार 11 जुलाई, 2024 • मूल्य : 1 रुपये • वार्षिक : 50 रुपये • पृष्ट : 4

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर मुख्यमंत्री को दिल्ली में किया गया सम्मानित

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डीपीएमआई सभागार न्यू अशोक नगर नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बडी संख्या में बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सभी ने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने राज्य विधान सभा में नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखण्ड की जनता का आशीर्वाद बताते हुये कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिये केन्द्र सरकार तथा प्रदेश की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि देश में सभी के लिये सभी के लिये समान कानून लागू करने का हमारा

संकल्प रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर देवभूमि की सवा करोड़ जनता से किये गए अपने वादे को निभाया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ''एक भारत और श्रेष्ठ भारत'' मन्त्र को साकार करने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना आशीर्वाद देकर पुन: सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार गठन के तुरंत बाद, जनता जर्नादन के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 02 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी तथा 7 फरवरी को विधान सभा द्वारा पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसकी नियमावली बनाने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस वर्ष अक्टूबर तक इसे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है उसी प्रकार राज्य विधान सभा से पारित समान नागरिक संहिता के रूप में निकलने वाली समान अधिकारों की संहिता रूपी ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा संविधान एक पंथनिरपेक्ष संविधान है। यह एक आदर्श धारणा है, जो हमारे समाज की विषमताओं को दूर करके, हमारे सामाजिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि माँ गंगा-यमुना का यह प्रदेश, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, ऋषि-मुनियों, वीर बलिदानियों की इस पावन धरती ने एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित होने के बावजूद अब तक इसे दबाये रखा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से माताओं-बहनों और बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। हमारी माताओं-बहन-बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। हमारी आधी आबादी को सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा देकर हमारी मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि एक वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष या अधिक का हो और वयस्क महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक की हो, वे तभी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे, जब वो पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में न हों और कानूनन प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में न आते हों। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव-इन में रहने हेतु केवल पंजीकरण कराना होगा जिससे भविष्य में हो सकने वाले किसी भी प्रकार के विवाद या अपराध को रोका जा सके।

म्येरू पहाड फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रो. दयाल सिंह पंवार, एडवोकेट श्री सतीश टम्टा, पूर्व आईएएस कुलानंद जोशी, श्री देवेन्द्र जोशी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला, प्रो ललिता गांधी, डश्व धर्मा रावत आदि उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड के सैन्य अधिकारी कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र से सम्मानित

देहरादून। उत्तराखंड के मेजर रविंद्र सिंह रावत के अद्वितीय साहस और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए भारत सरकार की ओर से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर रावत ने भारतीय सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स (राजपूत) में तैनात रहते हुए बहादुरी तथा प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन कर 11 सफल ऑपरेशन में भाग लिया और 28 आतंकवादियों के खात्मे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र, ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन के मेजर सचिन नेगी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

मूल रूप से चमोली जिले के गौचर (अंगोत) निवासी मेजर रावत ने 30 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के एक गांव में तीन हथियारबंद आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान मेजर रावत गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, लेकिन अद्वितीय साहस और अनुकरणीय नेतृत्व के दम पर उन्होंने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर रावत का परिवार सैनिक पृष्ठभूमि का है। उनके पिता बादर सिंह रावत कोर ऑफ सिग्नल्स से सेवानिवृत्त हैं। जबकि, दादा दिवंगत बालम सिंह रावत सेना से सेवानिवृत्त थे। बड़ी बहन शशि रावत भी इस वक्त आर्मी मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सेवारत हैं।

मंत्री अग्रवाल ने नम आंखों से दी वीर शहीद विनोद सिंह को अंतिम विदाई

ऋषिकेश। जम्मू के कठुआ में शहीद हुए भानियावाला के जवान विनोद सिंह का अंतिम सस्कार गंगा तट स्थित पूर्णानंद घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राज्य सरकार की ओर से क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद को अंतिम सलामी देकर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने वीर सपूत के बलिदान को याद कर डॉ. अग्रवाल भावुक नज़र आए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबाँकुरों ने उत्तराखण्ड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध हमारे वीर जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी क़ीमत पर बख्शे नहीं जाएँगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। सैन्यभूमि

उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि है। यहां के जवानों ने सदैव माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन किया है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि ज्ञाहीद जवानों का नाम भारत हमेशा याद रखेगा। संपूर्ण राज्य को अपने बेटों व भाइयों पर गर्व हैं। पांचों वीर जवान हमारे परिवार के सदस्य हैं। दु:ख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है।

शहीद विनोद सिंह की अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिला अध्यक्ष ;षिकेश रविन्द्र राणा, एसपी देहात देहरादून लोकजित सिंह, एडीएम जय भारत, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर देवेंद्र नेगी, पूर्व विधायक धन सिंह नेगी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष विनोद कुकरेती, देवेश उनियाल सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, शहीद के परिजन उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

तिरूपति की तर्ज पर हो तीर्थ सुविधाएं, यात्री संख्या पर रोक हटे !

● भूपत सिंह बिष्ट

उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम व्यवस्था से नाखुश चारधाम हितधारक संस्थाओं ने कैंट रोड़ के होटल में एक महाधिवेशन किया।

आयोजन में चारधाम होटल एसोसिएशन , चारधाम पंडा पुरोहित समाज संगठन , समस्त टूर ओपेरटर्स , व्यापार एसोसिएशन तथा टैक्सी - बस यूनियंस के पदाधिकारी शामिल थे।

मौजूदा चार धाम यात्रा पंजीकरण व्यवस्था का सबने एक सुर में विरोध किया।

चारधाम हितधारक संस्थाओं का मत रहा कि सरकार माता वैष्णों देवी धाम और तिरुपति धाम की तरह सुविधा जुटाए बाकि तीर्थ यात्रियों की संख्या पर अंकुश न लगाए।

हम चारधाम यात्रा के हितधारक विगत एक शताब्दी से इस यात्रा को सफल बना रहें हैं और आगे भी कृत संकल्पित हैं। केदार सभा के पदाधिकारी ने आशंका जाहिर कि केदारनाथ पुनर्निर्माण में मंदिर के वास्तु से छेड़छाड़ हो रही है। केदारनाथ के बर्फीले मौसम में तीन मंज़िल भवनों का निर्माण धन की बरबादी साबित होगा।

हर साल पिछले निर्माण को क्षति हो रही है। सरकार को तीर्थ यात्री और पर्यटक के अंतर को समझाना जरुरी है।

केदारनाथ धाम की शोभा तीर्थ यात्रियों से है - जिनका कार्यक्रम कई सप्ताह पहले तय होता है और इन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन में उलझना ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चार धाम यात्रा को पौराणिक परम्पराओं से चलाने व शंकराचार्य जी से मशविरा लेने के लिए ज्ञापन दिया जायेगा।

चारधाम यात्रा के मार्ग में परिवर्तन का विरोध किया जायेगा।

ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर अधिकारियों की मनमानी की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से की जायेगी।

चारधाम और यात्रा के पौराणिक स्वरुप को बचाने के लिए कोर्ट से लेकर सड़कों तक विरोध दर्ज कराएंगे।

महाधिवेशन में महंत अजय पुरी, काशी विश्वनाथ मंदिर , उत्तरकाशी, अभिषेक अहलुवालिया, बिक्रम राणा, अशोक सेमवाल सहित तीस हितधारक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे।

आल वैदर रोड़ में दरकते पहाड़ उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए नई चिंता की लकीरें खड़ा कर रहा है।

अब सरकार को यात्रा मार्ग पर बैरियर ठोकने के बजाये, पूरे यात्रा मार्ग पर भूस्खलन चेतावनी के यंत्र स्थापित करने जरूरी हो गए हैं।

एक बार फिर से 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद प्रस्तावित सावधानियों को चारधाम मार्ग पर सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए अनिवार्य हो गया है।

शिक्षा विभाग में शिकायतों के निवारण को बना कंट्रोल रूम

देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने बरसाती सीजन को देखते हुये समस्याओं के निवारण के लिये कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसके साथ ही विभाग ने टोलफ्री नम्बर भी जारी किया है। जिस पर छात्र-छात्राएं, अभिभावक व शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। जन समस्याओं के निराकरण के लिये विभाग ने नोडल अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित कर दी है ताकि शिकायतों व समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने मानसून सीजन को देखते हुये कांट्रोल रूम की स्थापना की है, ताकि बरसात के दौरान समाने आने वाली विभिन्न समस्या से तत्काल निपटा जा सके। इसके अलावा विभाग ने शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिये टोलफ्री नम्बर 18001804132 भी जारी किया है। जिस पर छात्र-छात्राएं, अभिभावक व शिक्षक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। टोलफ्री नम्बर पर दर्ज शिकायतों व समस्याओं के तत्काल निवारण के लिये विभाग ने नोडल अधिकारी, सह नोडल अधिकारी व 10 कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की है। जिसमें अजीत भण्डारी, प्रद्युमन रावत, पल्लवी नैन, अंजुम फातिमा, एम.एम. जोशी को नोडल जबकि हरीश नेगी, नूतन, विजयलक्ष्मी, पूनम व मुकेश कुमेड़ी सह नोडल होंगे। ये सभी कार्मिक 8 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक कंट्रोल रूम में बैठकर टोलफ्री नम्बर पर दर्ज समस्याओं व शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर विभागीय स्तर पर निवारण करेंगे।

इस संबंध में विभागीय मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिये हैं।

उन्होंने अधिकारियों को टोलफ्री नम्बर पर आने वाली प्रत्येक कॉल को रिसीव करने तथा प्रत्येक समस्या का समय पर समाधान करने को कहा। इसके साथ ही कांट्रोल रूम के सफल संचालन को प्रत्येक दो सप्ताह में समीक्षा करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियां को दिये हैं।

देहरादून में श्रीगुण्डिचा रथ यात्रा का भव्य आयोजन

देहरादून। श्री श्री जगन्नाथ जी श्रीगुण्डिचा रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस यात्रा के आयोजक शक्ति पुत्र पंडित एसपी सतपति ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की उपस्थिति में विधि विधान से पूजन कराकर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का राम मंदिर से शुभारंभ किया। भक्तजनों ने उत्साहपूर्वक रस्से खींचकर भगवान का रथ खींचा।

यात्रा श्री राम मंदिर, दीपलोक से प्रारंभ होकर श्री राधाकृष्ण मंदिर, किशन नगर चौक में भव्य स्वागत के बाद सैय्यद मौहल्ला, बिंदाल पुल, घंटाघर, पल्टन बाजार, धामावाला बाजार, हनुमान चौक, प्राचीन शाकुंबरी देवी मंदिर, सांई मंदिर, तिलक रोड होते हुए वापिस श्री राम मंदिर दीपलोक पहुंची। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी, श्री जगन्नाथ जी की आरती और मिलन के उपरांत श्री महाप्रसाद का वितरण किया गया।

इस आयोजन में मुख्य रूप से विधायक सविता कपूर, पुनीत मित्तल, मुकेश गर्ग, हरीश मित्तल, संस्था अध्यक्ष आरके गुप्ता, सचिव अरविंद मित्तल, सुनील गोयल, पूर्व पार्षद सचिन गुप्ता, अशोक वर्मा, अनुराग गुप्ता, मनोज शर्मा, परिवेश आदि हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।

दून को पेड़ों की छांव देने के लिए लगाए 11 हजार से ज्यादा पौधे

देहरादून। देहरादून को फिर से हराभरा बनाने के लिए उमेश अग्रवाल फाउंडेशन और एलोरास मेल्टिंग मोमेंट्स ने 'प्रोजेक्ट छांव' के अंतर्गत रविवार को बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया। राजकीय पश्चलिटेक्निक के पास, नाला पानी रोड, आमवाला, देहरादून शहर में लगभग 11 हजार से अधिक पौधे रोपे गए। इससे पहले इन संस्थाओं ने दून के विभिन्न इलाकों में तुलसी के 15 हजार पौधे बांटे। वहीं, इस पौधारोपण को जारी रखने तथा लगाए गए सभी पौधों की पांच साल तक देखभाल करने का निर्णय लिया गया है।ह

दून में इस साल तापमान पिछले वर्षो की तुलना में कहीं अधिक रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। इस समस्या का समाधान शहर को हरियाली का आवरण पहनाकर ही दूर किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उमेश अग्रवाल फाउंडेशन और एलोरास ने 'प्रोजेक्ट छांव' के संचालन का निर्णय लिया। अभियान में शहरवासियों को आमंत्रित किया गया था।

इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही, प्रोजेक्ट छांव का थीम सश्रंग लांच किया गया। वृहद पौधारोपण अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजक संस्थाओं ने जानकारी दी कि इस पहल से न केवल शहर की हरियाली बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस छोटी सी पहल से हम अपने शहर को और बेहतर और स्वच्छ-सुंदर बना सकते हैं। इस अभियान में सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है।

प्रोजेक्ट छांव की पहल को रायपुर विधायक उमेश शर्मा, राज्य मंत्री ज्योतिप्रसाद गैरोला, देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, प्रमुख व्यवसायी अनिल गोयल सहित शहर के बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग मिला।

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म

देहरादून। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में एक महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है। चकराता क्षेत्र की डोंडा गांव निवासी महिला ने सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा तीनों स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। तीन बच्चों को एक साथ जन्म देने का चकराता क्षेत्र में यह पहला मामला बताया जा रहा है। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ प्रेरक मित्तल ने माता पिता व परिवारजनों को बधाई एवम् शुभकामनाएं दीं।

चकराता तहसील के अन्तर्गत छावनी बाजार से सटी ग्राम पंचायत मगरोली के होडा गांव निवासी महिला ने एक साथ तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ प्रेरक मित्तल ने कहा कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के स्त्री एवम् प्रसूती रोग विभाग में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिलीवरी के लिए उत्तराखण्ड सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी डिलीवरी के लिए मामले श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में पहुंचते हैं। ऐसे मामलों में डिलीवरी संवेदनशील होती हैं। डिलीवरी के लिए उपलब्ध सभी अत्याधुनिक सुविधाएं एवम् कुशल डॉक्टरों की टीम ऐसी संवेदनशील डिलीवरी के मामलों को भी आसान बना देती है। नवजात बच्चों के पिता सशस्त्र सीमा बल में हवलदार के पद पर तैनात हैं। जैसे ही उन्हें अपनी पत्नी के सुरक्षित प्रसव की सूचना मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरन्त छुट्टी लेकर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल पहुंचे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला गांव में ही रहती हैं। बीते शुक्रवार उन्हं प्रसव पीडा उठी। इसके बाद परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के कुशल डॉक्टरों ने सफल सिजेरियन डिलीवरी करवाई। इसके बाद महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया, इसमें एक लड़का और दो लड़कियां शामिल हैं। महिला की यह पहली डिलीवरी है। अस्पताल में सुखद ट्रिप्लीकेट डिलीवरी का मामला मरीजों और अस्पताल स्टाफ के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

वहीं तीन बच्चों को जन्म देने के बाद परिवार सहित पूरे गांव में खुशी का माहौल है। परिजनों ने जानकारी दी कि डिलीवरी के बाद तीनों बच्चे व मां पूरी तरह स्वस्थ हैं।

उत्तराखंड में सिविल सेवा परीक्षा के लिए शासन ने जारी किए सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 14 जुलाई 2024 को प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के सफल एवं शुचितापूर्ण आयोजन हेतु इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि 14 जुलाई 2024 को प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में तैनात समस्त अधिकारियों एवं जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र पर्यवेक्षकों की परीक्षा से 02 दिन पूर्व ब्रीफिंग समस्त जिलाधिकारियों / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/ पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में आहूत की जाये जिसमें सभी केन्द्र व्यवस्थापक अनिवार्य रूप से भाग लें। बैठक में केन्द्र पर्यवेक्षकों / व्यवस्थापकों को परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु वांछित उपाय सख्ती से बरतने के निर्देश जारी किये जायें।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा प्रक्रिया के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्र पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाये कि वह सभी कक्ष निरीक्षकों, सचल दल एवं तैनात अन्य समस्त कार्मिकों को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सचेत करेंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा से सम्ब) किसी भी स्तर पर शिथिलता परिलक्षित होने पर इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तदनुरूप कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी सभी उपलब्ध माध्यमों से जिले भर में प्रसारित की जाये, ताकि अवांछित तत्वों में प्रशासन की मुस्तैदी का प्रभाव बना रहे। जनपदों के सभी परीक्षा केन्द्रों का संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करते हुये परीक्षा तिथि को इनमें सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा फ्लाइंग स्क्वाड अतिरिक्त पुलिस बल / अभिसूचना कार्मिक तैनात किये जायें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि दूरस्थ एवं संवेदनशील केन्द्रों में पृथक से डेडिकेटेड सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सतत निगरानी की जायेगी। केन्द्रों में संबंधित सैक्टर मजिस्ट्रेट प्रश्नपत्रों, परीक्षा सामग्री का प्रति पाली पृथक-पृथक संकलित करते हुए पृथक से जमा करेंगे। परीक्षा तिथि के पूर्व से ही स्थानीय अभिसूचना इकाईयाँ / एजेंसीज सक्रिय बनी रहें। संज्ञान में आया है कि जनपदों में परीक्षाओं के संचालन में तैनात कतिपय सैक्टर मजिस्ट्रेट केवल गोपनीय सामग्री को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने व वापस संबंधित डाकघर तक लाने में ही व्यस्त रहते हैं। अत: परीक्षा केन्द्रों पर व्यापक पर्यवेक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य जनपदीय अधिकारियों को भी उक्त कार्य हेतु तैनात किया जाये तथा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी परीक्षा अवधि में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आवश्यक रूप से भ्रमण एवं निगरानी करना सुनिश्चित करें। वर्षाकालीन मौसम के दृष्टिगत आवागमन सुचारू बनाए रखने हेतु अवरूद्ध मार्गो को तत्परता से खोलने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

धाद का हरेला अभियान 14 जुलाई को

देहरादून। सामाजिक संस्था धाद ने अपने एक माह तक चलने वाले हरेला अभियान का शुभारम्भ देहरादून में उत्तराखंड हिमालय के गांव उसकी खेती और शहरों की हरियाली पेड़ों के सवाल पर नागरिक मार्च के साथ करने का तय किया है धाद ने आम समाज से हरेला के माह एक पौधा लगाने और उसके वृक्ष बनने की जिम्मेदारी लेने के साथ अपने आस पास के पेड़ो का ध्यान रखने उनकी रक्षा करने और हिमालय उपज को आपने जीवन में शामिल करने की अपील की है संस्था द्वारा हरेला अभियान की जानकारी तन्मय, सुशील और आशा डोभाल द्वारा दी गयी।

धाद के हरेला अभियान की जानकारी देते हुए धाद के सचिव तन्मय ने कहा पिछले चौदह वर्षो से धाद ने उत्तराखंड के लोकपर्व हरेला को व्यापक सामाजिक सन्दर्भ के साथ समाज और शासन में स्थापित करने की पहल की है। इस वर्ष इस परंपरा को जारी रखते हुए 14 जुलाई को हरेला मार्च के साथ हरेला अभियान शुरू होगा जिसका समापन घी संग्रांद पर पहाड़ के अन्न और भोजन के साथ होगा। धाद के साथी आम समाज के साथ वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सवालों और उत्तराखंड हिमालय के उत्पादन के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए गतिविधि करेंगे। पेड़ सभा, गीत संध्या के साथ उत्तराखण्ड के गाँव के उत्पादन और उसके सवालों के साथ शहरी

क्षेत्रों में घट रहे पेड़ों और हरियाली के पक्ष में सेमिनार आयोजित किये जाएंगे अभियान स्कूल, संस्थान मोहल्ले में धाद के साथी सभाएं करेंगे।

हरेला गाँव के संयोजक हरीश डोबरियाल की तरफ से कहा गया कि हरेला जो मूलत: खेती और उसके उत्पादन का पर्व है अब जबकि इसने व्यापक रूप ले लिए है तब जरुरी है कि उत्तराखण्ड हिमालय की खेती उसके उत्पादन के सवाल सामाजिक विमर्श के केंद्र में आये। लगातार घटते हुए कृषि क्षेत्र और बंजर होती जमीनेह्न आज एक बड़ा सवाल है इसलिए हरेला गाँव के अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ गाँव के साथ सामजिक प्रयोग करते हुए उनके उत्पादन को मजबूत करने और उसे सही बाजार दिलवाने के लिए काम करना प्रारम्भ किया है। इसके पक्ष में हरेला के माह एक बड़ा सम्मलेन हरेला गाँव सतपुली पौड़ी में प्रगतिशील किसानों के साथ किया जाना है।

ट्रीज ऑफ़ दून के संयोजक हिमांशु आहूजा ने कहा शहरों के विकास और लगतार बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव ने शहर और उसके आस पास मौजूद पेड़ों पर सीधा असर किया है।हम हरेला में पेड़ देहरदून के अध्याय के अंतर्गत पेड़ सभाये करेंगे और उनकी इस शहर को बनाने और उसकी आबो हवा के लिए की गयी भूमिका को सबस साझा करेंगे साथ ही शहर के पुराने वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित करने का प्रस्ताव शासन को दिया जाएगा।

हरेला स्कूल की संयोजक आशा डोभाल ने बताया सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों के साथ हम एक कोना कक्षा का कार्यक्रम के तहत हरेला मनाते आये हैं। जिसमे प्रदेश के 700 से अधिक स्कूल शामिल है। इस वर्ष से आम समाज के सहयोग को स्कूलों में बाल वन बाल वाटिका विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिसमे स्कूल और उसके छात्रों को उनके प्रांगण में पौधों से पेड़ों के विकास के लिए सार्वजनिक रूप से पुरुस्कृत किया जाएगा।

हरेला देश दुनिया के संयोजक दयासागर धस्माना ने कहा कि हरेला का विचार उत्तराखंड के समाज को एक वैक्विक पहचान दिलाने की समर्थ्य रखता है उत्तराखडं की एक बड़ी आबादी हरेला जो देश विदेश में रह रही है वह हरेला के साथ जुड़कर देश दुनिया को एक हरी भरी दुनिया का सन्देश दे सकता है।

आपदा से निपटने मे विभाग पूरी तरह सक्षम पूर्व मंत्री की आशंका फिजूल : चौहान

देहरादून। भाजपा ने आपदा को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए, हर परिस्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने का दावा किया हैं। साथ ही पलटवार किया कि आपदा प्रबंधन विभाग का प्रत्येक कर्मचारी पूर्णतया सक्षम है और जनसहयोग से अपना सौ फीसदी योगदान दे रहा है। कभी विभाग में मंत्री रहे विपक्ष को संदेह हो सकता है लेकिन सरकार और जनता दोनों को सभी आपदा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने स्पष्ट किया कि आपदा सीजन के चलते प्रत्येक छोटे से छोटा नुकसान रोकने की हमारी सरकार मंशा रखती है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समस्त आपदा प्रबंधन तंत्र, चाहे वह पुलिस या दमकल विभाग हो, चाहे एसडीआरएफ या एनडीआरएफ हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो या अन्य सभी जरूरी विभाग पूरी क्षमता से आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने में जुटे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ा चढ़ा कर झूठे आरोप तो लगाए लेकिन एक भी ठोस परिणाम उसके पक्ष में नहीं दे पाए । क्योंकि वे भी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि सरकार की तैयारियों और आपदा के प्रभाव को कम करने की गंभीर कोशिशों का ही नतीजा है कि किसी बड़े नुकसान से राज्य

अब तक प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनसहयोग से राज्य को आपदा से सुरक्षित रखने की सरकार की कोशिशें अवश्य सफल होंगी।

चौहान ने पलटवार किया कि विपक्ष आपदा प्रबंधन विभाग की क्षमता पर संदेह जता कर भय का वातावरण उत्पन्न कर राज्य की छवि खराब करना चाहता हैं। जबकि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता और नीयत पर पूरा भरोसा है।

मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कर्मचारी ही नही बल्कि प्रदेश का हर शख्स आपदा का सामना करने के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। बेहतर होता कि जिन्होंने सत्ता में रहते आपदा नियंत्रण को लेकर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया और स्वयं आपदा विभाग का मंत्री होने पर भी जिन्हे उस पर ही भरोसा नहीं हो, उन्हे कम से कम आज की परिस्थितियों में सकारात्मक सहयोग करना चाहिए।

विभागीय मंत्री ने दिये निर्देश : जनपदों में निजी पैथोलॉजी लैब्स की जांच करेंगे सीएमओ

देहरादून। राज्य में अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दे दिये गये हैं। विशेष रूप से मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में मानकों के विपरीत संचालित पैथोलॉजी सेंटरों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये हैं।

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि पैथोलॉजी लैब में जांच के नाम पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो इसके लिये प्रदेशभर में निजी पैथोलॉजी लैब्स का सत्यापन किया जायेगा। डा. रावत ने कहा कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से अवैध पैथोलश्वजी लैब संचालन की शिकायतें मिली हैं। शिकायतकर्ताओं ने जिन तथ्यों को सामने रखा है वह मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंताजनक है।

डा. रावत ने बताया कि अनाधिकृत रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब व ब्लड कलेक्शन सेंटरों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रदेशभर में सत्यापन अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने बताया कि विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जनपद में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब व सेंटरों के संचालन की शिकायतें मिली हैं। जिनमें मानकों के अनुरूप टेक्नीकल स्टॉफ व डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं ये निजी पैथोलॉजी लैब क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी पंजीकृत नहीं है। अवैध रूप से संचालित इन पैथोलॉजी लैब की जांच के लिये संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि अवैध पैथोलॉजी केन्द्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ताकि मरीजों के रक्त जांच की प्रमाणिकता और गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके।

विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य में पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिये क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है, इसके साथ ही मेडिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दस्तावेज भी होने जरूरी है।

उन्होंने बताया कि पैथोलॉजी लैब में कार्यरत डश्वक्टरों का उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल तथा टेक्नीशियनों का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है। डा. रावत ने कहा कि जो पैथोलॉजी लैब और ब्लड कलेक्शन सेंटर मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

वित्त मंत्री ने दी मरीजों को राहत चिकित्सा सेवा शुल्क किया कम

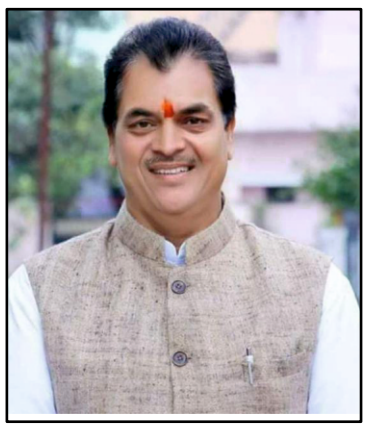

देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं एंबुलेंस और बैड चार्जेज भी कम देना होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा। जिससे जनसामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा।

वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किये जाने का विचार किया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रूपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रूपये किया गया हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रूपये से 10 रूपये, जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रूपये से 20 रूपये किया गया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अभी तक 17 रूपये लिया जा रहा है, जिसे अब 15 रूपये किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रूपये से 25 रूपये जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रूपये से 50 रूपये किया गया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को 05 किलोमीटर तक 315 रूपये न्यूनतम रूपये एवं अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रूपये प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है, जिसे 05 किलोमीटर तक 200 रूपये न्यूनतम तथा अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रूपये प्रति किलोमीटर किया गया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डा. अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य में यूजर्स चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं जाएगी। इसके विपरीत आम जनमानस एवं रोगियों के हित में यूजर्स चार्जेज में तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक जताया

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। ऐसी आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।'' (भाषा)

पंचतत्व में विलीन हुई विधायक शैलारानी रावत अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, बेटी और भतीजे ने दी मुखाग्नि

रूद्रप्रयाग। केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत पंचतत्व में विलीन हो गई। रुद्रप्रयाग में विद्यापीठ स्थित त्रिवेणी घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। बेटी एश्वर्या और भतीजे शैलेंद्र रावत ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी।

कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक को पुष्पचक्र भेंटकर श्रद्धांजलि दी। वहीं, पुलिस की टुकड़ी ने हथियार झुकाकर विधायक को अंतिम विदाई दी।

बृहस्पतिवार सुबह विधायक शैलारानी रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से खेल मैदान में लाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने भी विधायक को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जयकारों के बीच विधायक का पार्थिव शरीर लेकर वाहन त्रिवेणी घाट के लिए रवाना हुआ। दोपहर बाद करीब डेढ़ बजे शव यात्रा त्रिवेणी घाट पहुंची।

इसके बाद कर्मकांड की सभी परंपराओं के निर्वहन के बीच विधायक की बेटी एश्वर्या और भतीजे शैलेंद्र ने मुखाग्नि दी।

इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा के विकास को लेकर शैलारानी ने जो सपना देखा था, उसे साकार करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

एम्स में अब प्रत्येक रोगी की होगी टी.बी. की जांच

एम्स ऋषिकेश। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एम्स ऋषिकेश ने अब प्रत्येक रोगी में क्षय रोग की जांच करने का निर्णय लिया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित ओपीडी में आने वाले प्रत्येक रोगी को इसके दायरे में लाया जायेगा।

भारत सरकार के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अनुरूप एम्स ऋषिकेश अब अस्पताल में आने वाले सभी रोगियों के लिए अनिवार्य रूप से तपेदिक (टीबीऋ)की जांच शुरू करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में टीबी (क्षय रोग) पर नियंत्रण और उसका शीघ्र निदान व उपचार को सुनिश्चित करना है।

इस संबन्ध में जानकारी देते हुए एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने बताया कि नयी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने और रोगी को चिन्हित करने के लिए विशेष फार्मेट तैयार किया गया है। प्रोटोकॉल के तहत बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी), विभिन्न वार्डो (आईपीडी) और विशेष क्लीनिकों में आने वाले सभी रोगियों से टीबी लक्षणो के

बावत व्यापक पूछताछ कर उक्त फॉर्मेट में अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड के जारी निर्देशों के अनुपालन में ओपीडी में आने वाले प्रत्येक रोगी की जांच और उसे आवश्यक परामर्श देते वक्त सम्बन्धित डॉक्टर द्वारा रोगी से टीबी के लक्षणों के बारे में भी पूछा जायेगा। प्राप्त लक्षणों के आधार पर डॉक्टर को टीबी मरीजों के पर्चे पर मुहर लगानी होगी ताकि चिन्हित रोगी का इलाज समय रहते शुरू किया जा सके।

प्रो. मीनू सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य टीबी के संकेत देने वाले किसी भी लक्षण की पहचान करना समय पर निदान और पर्याप्त इलाज की सुविधा प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि एम्स के पल्मोनरी विभाग के अधीन संचालित ओपीडी में टीबी रोगियों की जांच और उनके उपचार की सुविधा पहले ही उपलब्ध है। अब संस्थान की यह नयी पहल तपेदिक से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध हो सकेगी।

बेटे की चाह रखने वाले पिता ने जुड़वां नवजात बेटियों को मारकर दफनाया

नयी दिल्ली। सुल्तानपुरी इलाके में बेटे की चाह रखने वाले 32 वषह्य एक व्यक्ति ने अपनी तीन दिन की जुड़वां बेटियों की कथित तौर पर हत्या कर दी और उन्हें अपने घर के पास दफना दिया। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली महिला ने दिल्ली पुलिस में एफआइआर दर्ज करवाते हुए कहा कि उसके पति व ससुराल वाले लड़कियों के जन्म से नाखुश थे और जन्म के तत्काल बाद बच्चियों को ले गए, बाद में कहा कि उनकी बीमारी से मौत हो गई। पुलिस ने बच्चियों के शवों को बाहर निकलवा लिया है।

इस पर पुलिस ने एसडीएम की निगरानी में बच्ची के शव को शमशान घाट से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहा जा रहा है कि लड़की पैदा होने की वजह से आरोपी पिता ने ऐसा किया।

पुलिस अधिकरी ने बताया कि आरोपी नीरज सोलंकी को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया है ।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सुबोध भट्ट द्वारा दून वाणी प्रिंटर्स डी0एल0 रोड, देहरादून से मुद्रित एवं मोहकमपुर कलां, माजरी मी, पो0ओ0 नवादा, देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित।
सम्पादक : सुबोध भट्ट मो0 9837383994, email : subodhbhatt09@gmail.com
Web site : harshitatimes.com, facebook page : harshitatimes.com, email : harshitatimes09@gmail.com,